मुख्य सचिव, उत्तराण्ड शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक दिनांक 19 जुलाई,2018 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–संलग्न है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक में डा० तारसेम चन्द, संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया गया। बैठक में श्री डी० सेन्थिल पाण्डियन, सचिव, कृषि एवं उद्यान; श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विकास; श्री एस० ए० मुर्गेशन, जिलाधिकारी देहरादून; श्री ललित मोहन रयाल, गन्ना आयुक्त, के साथ ही कृषि, पशुपालन, उद्यान, रेशम एवं अन्य संबंधित विभागों के निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक तथा अन्य प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

एजेण्डा नं०–1 गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

सचिव कृषि द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक की कार्यवाही पटल पर रखी गयी, सदस्यों द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विभिन्न स्तरों पर आयोजित समीक्षा बैठक, राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति (SLPSC), प्री–एस०एल०एस०सी० (Pre-SLSC) तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठकों का विवरण प्रस्तुत किया गया। वर्ष में इस प्रकार कुल 12 बैठकें की गयी।

एजेण्डा नं०–2 योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं उपयोग

(1) कृषि निदेशक द्वारा योजना के प्रारम्भ वर्ष 2007–08 से वर्ष 2017–18 तक वर्षवार प्राप्त धनराशि एवं उसके उपयोग की स्थिति रखी गयी। वर्ष 2016–17 तक प्राप्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है, जिसके उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि एवं व्यय की समीक्षा की गयी। वर्ष 2017–18 में राज्यांश एवं केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 8988.44 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष रू० 5419.17 लाख का उपयोग किया गया है, जो कि प्राप्त धनराशि का 60 प्रतिशत है। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। रू० 3569.27 लाख अवशेष है, इस संबंध में कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से केन्द्रांश रू० 2915.40 लाख 31 मार्च 2018 को अन्तिम समय में प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि न होने के कारण आहरण नहीं हो पाया, यह धनराशि माह जून एवं जुलाई में अवमुक्त हुई है, फलस्वरूप धनराशि अवशेष रही है। अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि का उपयोग माह सितम्बर 2018 तक कर लिया जाएगा। निर्देश दिए गए कि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग समय से करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत

सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए, ताकि भारत सरकार के स्तर से धनराशि का आवंटन समय से हो सके।

(2) वर्ष 2017–18 में 15 कार्यदायी विभागों एवं संस्थाओं को आंवटित धनराशि तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। सभी विभागों के पास धनराशि अवशेष है, स्पष्ट है कि विभागों द्वारा समय से धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार को रू० 20.00 लाख, कैप सेलाकुई को रू० 200.00 लाख, एन.आई.आर.डी. हैदराबाद को रू० 100.00 लाख उपलब्ध कराया गया था, परन्तु इन विभागों/संस्थाओं द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी। संबंधित विभाग दो माह के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग करना सुनिश्चित करें। अन्य 12 कार्यदायी विभागों/संस्थाओं के पास भी धनराशि अवशेष है। ये विभाग शीघ्र अवशेष धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल विभाग को उपलब्ध कराएं।

एजेण्डा नं०–3

वर्ष 2018–19 हेतु प्राप्त आवंटन, वर्ष 2018–19 के लिये धनराशि की मांग, एवं वर्ष 2018–19 में प्राप्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति

(1) वर्ष 2018–19 हेतु प्राप्त आवंटन–भारत सरकार के पत्र संख्या–7-1/2018-RKVY दिनांक 14 मई, 2018 के द्वारा रू० 2127.00 लाख का आंवटन किया गया है। 10 प्रतिशत राज्यांश रू० 236.35 लाख सम्मिलित करते हुए वर्ष 2018–19 का कुल आवंटन रू० 2363.35 लाख होता है। जिसमें सामान्य आर०के०वी०वाई० (Normal RKVY) मद में रू० 1811.12 लाख, अनुसूचित जाति (SCP) मद में रू० 478.89 लाख तथा अनुसूचित जनजाति (TSP) मद में रू० 73.89 लाख आवंटन है।

(2) वर्ष 2018–19 के लिये धनराशि की मांग–सचिव कृषि द्वारा स्थिति रखी गयी कि योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत, वर्तमान संचालित 46 परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए रू० 19136.86 लाख की आवश्यकता है तथा वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त 17 नई परियोजनायें रू० 5746.17 लाख स्वीकृत हुई है। इस प्रकार पूर्व में स्वीकृत, वर्तमान में संचालित तथा नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कुल रू० 24883.03 लाख की आवश्यकता है।

(3) वर्तमान में संचालित (Ongoing) परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था –पूर्व से स्वीकृत परियोजनायें जो कि वर्तमान में संचालित (Ongoing) हैं, की समीक्षा की गयी। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु रू० 19136.86 लाख की आवश्यकता है, जबकि वर्ष 2018–19 के लिए रू० 2363.35 लाख मात्र का आवंटन है। धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए चर्चा के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

I. जो परियोजनायें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, एस०एम०एस०पी० एवं एस०एम०ए०एम० आदि से संचालित की जा सकती हैं, ऐसी

परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हटाकर, संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत गाईडलाईन के अनुसार कार्य कराए जाएं।

II. ऐसी स्वीकृत परियोजनायें जिन्हें अभी तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है, उन्हें धनराशि अवमुक्त न की जाए।

III. सगन्ध पौध केन्द्र सेलाकुई की परियोजना "PROMOTION OF MODEL AROMA CLUSTER IN HILL OF UTTARAKHAND" पर निर्णय लिया गया कि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा परियोजना संचालन हेतु दी गयी संस्तुति को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित करते हुए भारत सरकार से 15 दिनों के अन्दर सहमति प्राप्त कर ली जाए।

IV. ऐसी परियोजनायें जो सीधे कृषकों से संबंधित हों तथा जिनसे कृषकों की आय में वृद्धि होती हो, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

V. किसी भी परियोजना की परियोजना लागत में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्वीकृति की सीमा से अधिक धनराशि का कार्य नहीं किया जाएगा तथा समस्त कार्य परियोजना के लिए निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों/कार्ययोजना एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत किए जाएगें।

VI. उक्त चर्चा के क्रम में वर्ष 2018–19 में आंवटित/प्राप्त धनराशि वर्तमान में संचालित (Ongoing) निम्न परियोजनाओं के लिए उनकी अवशेष धनराशि के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आंवटित की जाएगी :–

वर्तमान में संचालित (Ongoing) परियोजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकता

(धनराशि लाख रू०)

S. N.	Departmnet	Name of Project	Sanction Year	Approved Amount	Total Release Amount	Total Expenditure Amount	Amount Required for completion of Project
1	Horticulture	Infrastructure Development Of Horticulture Input Centres	2014-15	137.33	68.00	50.00	69.33
2	UOCB	Saturation of selected blocks under organic farming.	2013-14	1247.24	387.36	517.36	659.88
3		Saturation of selected blocks under organic farming phase-II Year 2015-16.	2014-15	2667.88	437.56	385.56	2230.32
4		Support for continuing Farmers and Area under Organic regime identified by the UOCB in various schemes.	2017-18	728.20	260.00	151.00	468.20
5		Support for Marketing and Promotion of Organic produce from Uttarakhand.	2017-18	223.75	75.00	68.00	148.75
6	Sericulture	Development of four mulberry & one muga cluster during 2015-16 & 2016-17 in five District of Kumaun & Garhwal.	2014-15	804.37	612.55	612.55	191.82

S. N.	Departmnet	Name of Project	Sanction Year	Approved Amount	Total Release Amount	Total Expenditure Amount	Amount Required for completion of Project
7		Strengthening of Chawki rearing centre and capacity building of silkwarm rearrer for silk production .	2017-18	267.50	134.00	89.50	133.50
8		Proposal for Establishment of New Mulberry Cluster Nanak Matta-Sitarganj (Udhasinghnagar)	2017-18	166.00	80.00	55.70	86.00
9	Animal Husbandry	Foot & Mouth Disease Control Programme	2017-18	345.54	175.54	87.77	170.00
10	Sheep & Wool Developmen t board	Ahilya Bai Holkar Yojana for Sheep and Goat Development	2014-15	668.50	270.00	219.00	398.50
11		Proposal for strengthening, Mechanization and Automation of Govt. Sheep Breeding Farm Kedarkantha, Chamoli	2017-18	249.08	61.87	25.00	187.21
12		Proposal for strengthening, Mechanization and Automation of Govt. Sheep Breeding Farm Pipalkoti, Chamoli	2017-18	250.60	100.23	60.23	150.37
13		Proposal for strengthening, Mechanization and Automation of Govt. Goat Breeding Farm Dunda, Uttarkashi	2017-18	258.46	86.00	46.00	172.46
14	Mandi Prishad	Construction of mandi yard at Goverdhanpur, Laksar, District Haridwar.	2014-15	668.65	632.99	448.88	35.66
15		Setting up of a new Wholesale Market For Agricultural And Horticultural Produce at Narender nagar, Tehri.	2017-18	929.55	250.00	125.00	679.55
16		Construction of Fish Market at New Mandi Yard Mangalore.	2014-15	416.62	188.23	55.00	228.39
17	Bharsar University	Establishment of Germplasm centre with nursery of walnut other nuts and apricots.	2013-14	208.92	89.20	69.20	119.72
18	NSC	Erecting Chain Link Fencing of Vegetable Seed Production & Development of Neem Forest in Nearby hill Forest in Nainidanda Block of Pauri District.	2014-15	524.20	424.00	408.79	100.20
19	NBB	Integrated development of scientific beekeeping by adopting culster/area/ district development approach for enhancing crop productivity & income of beekeepers/farmers and generating employment in Kumaon division Uttarakhand.	2014-15	1115.67	50.00	50.00	1065.67
20	Dairy	Strengthening of Dairy Infrastructure at Haridwar Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. (Shikarpur Haridwar).	2013-14	417.23	279.90	280.00	137.33

S. N.	Departmnet	Name of Project	Sanction Year	Approved Amount	Total Release Amount	Total Expenditure Amount	Amount Required for completion of Project
21		Renovation of the Dehradun dugdh sangh dairy plant.	2013-14	578.52	7.94	7.94	570.58
22		Construction of over head RCC water reservoir and SMP godown at Nainital DUSS ltd., Lalkua, Nainital.	2013-14	104.76	98.39	98.39	6.37
23		Strengthening of Milk Processing & Products Manufacturing Infrastructure and maintaining Quality Standards of Cooperative Society in Uttarakhand.	2017-18	462.67	230.91	115.00	231.67
24	ULDB	Projects proposal for establishment of automatic compact fodder block manufacturing units at syampur, Rishikesh & rudrapur, US Nagar.	2013-14	968.36	968.21	968.21	0.15
25		By-pass protein supplement feed manufacturing plant at Kalsi	2013-14	532.11	0.00	0.00	0.00
26	Agriculture	Integrated Farming System Based Multipurpose Water Harvesting Projects Kumoun Mandal	2014-15	2119.08	2050.08	1932.00	69.08
27		Integrated Farming system based on Multipurpose Water Harvesting Project, Garhwal Division	2011-12	1433.90	1287.60	1287.60	146.30
28		Promotion of Farm Mechanization 2014-15	2014-15	2397.82	1650.00	1519.25	747.82
29		Integrated Project of Agriculture & Soil Conservation	2014-15	3528.93	1934.82	1564.82	1594.11
30		Soil Conservation Work Due to heavy rain on Dated 14-15 August 2014	2014-15	2134.90	950.00	941.50	1184.90
31		Protection of Agriculture Land & Crops From Wild Animals in Uttarakahnd	2014-15	5371.07	2650.00	2275.00	2721.07
32		Support for Construction of Farmers/Women and Youth Multipurpose Training Extension Information Centre of Excellence	2016-17	298.07	239.00	214.00	59.07
33		Hill Seed Bank in Uttarakhand Hills (Seed Production Programme)	2017-18	767.48	525.00	100.00	292.48
34		Crop Production Programme- Rice and Wheat (Rabi 2017 & Kharif & Rabi 2018-19 to 2019-20)	2017-18	612.44	265.00	70.00	347.44
35		Project proposal on Adoption and Certification under Organic Farming	2017-18	1200.00	400.00	300.00	800.00

S. N.	Departmnet	Name of Project	Sanction Year	Approved Amount	Total Release Amount	Total Expenditure Amount	Amount Required for completion of Project
36		Construction of Seed Testing Laboratories at Directorate of Uttarakhand Agriculture Campus.	2017-18	75.92	75.92	20.00	0.00
37		Construction of seed storage godown at Nyaypanchayat & Block of Uttarakhand.	2017-18	307.76	154.00	85.00	153.76
38		Centre of excellence of organic farming at Tehri	2017-18	498.43	0.00	0.00	498.43
39	CAP	Promotion of Model Aroma Clusters in Hills of Utttarakhand.	2017-18	949.16	200.00	0.00	749.16
40	TDC	Seed multiplication of crop varieties suitable for hills in Uttarakhand	2013-14	286.71	103.67	103.67	183.04
41	Sugar Cane	Sugar cane development programme (4 yrs)	2013-14	523.54	146.76	146.76	376.78
42	Fisherise	Trout Farming Project	2017-18	324.00	80.00	40.00	244.00
43	C-MAP	Introduction and popularization of newly developed cold tolerant menthol-mint variety CIM-Kranti among the farmers of Uttarakhand for income generation and agriculture intensification of research centre Pantnagar PO-Dairy farm Nagla District Udhamsingh nagar	2016-17	24.00	9.00	9.00	15.00
44	NIRD	Agro-Climatic planning and information bank (APIB) for Uttarakhand State	2017-18	294.61	100.00	0.00	194.61
45	Agriculture	Swachchta Action Plan-Namami Gange Clean Abhiyan	2017-18	634.18	150.00	17.85	484.18
Contingency					254.57	204.04	34.00
Total					19193.3	15824.57	19136.86

(4) **वर्ष 2018–19 में प्राप्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति–** राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति (SLPSC) द्वारा विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं की 23 परियोजनायें वर्ष 2018–19 के लिए ली गई। इन परियोजनाओं का परीक्षण भारत सरकार के स्तर पर किया गया तथा भारत सरकार के स्तर पर आहूत प्री–एस०एल०एस०सी० (Pre-SLSC) बैठक में रू० 5746.17 लाख की 17 परियोजनाओं पर सहमति प्रदान की गयी। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार से धनराशि का आवंटन मात्र रू० 2363.35 लाख है, जो कि आवश्यकता से काफी कम है। अतः धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए नई परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। भविष्य में वर्तमान में संचालित परियोजनाओं (Ongoing) के पूर्ण होने के उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने पर नई परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। केवल रबी एवं खरीफ में आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव कार्यक्रम, जो कि कृषि एवं कृषि से संबंधित सभी रेखीय विभागों से संबंधित है तथा राजकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार तथा कृषकों वैज्ञानिको के मध्य सीधे

संवाद का सशक्त माध्यम है, के लिए प्रस्तावित रू० 280.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष 16 नई परियोजनाओं पर केवल सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

वर्ष 2018–19 में प्राप्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

Department	S. N.	Project Name	Stream	Project Duration Year	Approved Project Cost	Remarks
Horticulture	1	Construction of horticulture hut and canteen at dhanaulti block-chamba tehri garhwal	Infrastr ucture	1 Year	104.27	Committee Approved In Principle as per State PWD norms.The detailed cost breakup duly verified by the administrative head of the concerned institution and the administrative head of the State Department concerned must be included in the project proposal.
	2	Construction of Mali training centre at Gaza block-chamba tehri garhwal	Infrastr ucture	1Year	318.81	Not Approved. May be taken up under some other Schemes.
Sericulture	3	Intensive Bivoltine sericulture Development under RKVY	Flexi fund	2 Year	350.32	Committee In Principle Approved as per CSB & MIDH Norms.
Animal Husbandry	4	Compact mobile diagnostic laboratories in Uttarakhand state	Infrastr ucture	2 Year	140.00	Approved In Principle. Subject to the condition that there is no duplication of activities under other LH & DC scheme however DPR should be submitted to DAHD&F
	5	Construction of egg holding room and feed store in three poultry farms of uttarakhand	Infrastr ucture	1 Year	36.08	Approved In Principle
	6	Increasing herd strength of govt. piggery farm kashipur	Infrastr ucture	1Year	6.70	Approved In Principle
	7	Strengthening of government piggery farm kashipur	Infrastr ucture	1Year	17.44	Committee In Principle Approved as per State PWD norms. The detailed cost breakup duly verified by the administrative head of the concerned institution and the administrative head of the State Department concerned must be included in the project proposal.
	8	Strengthening of state poultry farm Kotdwar Uttarakhand	Infrastr ucture	1 Year	72.10	Committee Approved In Principle & advised the detailed cost breakup duly verified by the administrative head of the concerned

Department	S. N.	Project Name	Stream	Project Duration Year	Approved Project Cost	Remarks
						institution and the administrative head of the State Department concerned must be included in the project proposal.
Mandi Parishad	9	Setting up of a new wholesale market for apple and other prishables at arakot, uttarkashi	Infrastr ucture	2 year	0.00	Approved in Principle as availability of funds and providing undertaking for running of Market.
UUH&F Bharsar University	10	Reponses of amaranth-lentil cropping system to different locally available sources of organic nitrogen in hills ofUttarakhand	Flexi fund	3 Year	0.00	Not Approved
Dairy	11	Strengthening of milk chilling processing and cattle feed manufacturing infrastructure in Uttarakhand	Infrastr ucture	1 Year	349.00	Approved in Principle civil work cost as per PWD Norms & procurement as per State Govt. Rule.
Fisheries	12	Project on trout farming	Infrastr ucture	3 Year	157.50	Approved in Principle as per Blue Revolution norms.. DBT may be done and contribution of share by therespective stakehorder
	13	Project on pangasius farming	Infrastr ucture	3 Year	125.00	Not Approved
ULDB	14	Establishment of Training Centre at animal breeding farm Nariyalgaon Village.	Infrastr ucture	2 Year	217.00	Committee Approved in Principle as per State PWD norms. The detailed cost breakup duly verified by the administrative head of the concerned institution and the administrative head of the State Department concerned must be included in the project proposal.
	15	Strengthening of animal housing and semen lab facilities at deep frozen semen production centre, shyampur, Rishikesh by year 2022-23	Infrastr ucture	5 Year	310.75	Approved in Principle that. Duplication with other GOI/ State Scheme may be avoided. Scheme should be recast for 2 years.
Agriculture	16	Krishak Mahostav rabi 2018 Khari 2019	Flexi fund	2 Year	280.00	Approved as per ATMA norms.

Department	S. N.	Project Name	Stream	Project Duration Year	Approved Project Cost	Remarks
	17	Integrated soil & water conservation work in Uttarakhand	Infrastr ucture	2 Year	1919.56	In Principle Approved as per norms of IWMP PMKSY- Per Drop More Crop (other Intervention), PMKSY-Har Khet koPani and MIDH (Poly House) after inclusion in DIP/ SIP of the State and AAP of PMKSY. Geo tagging may be done
	18	Construction of collection centre & mini cold room	Infrastr ucture	2 Year	913.79	In Principle Approved as per MIDH norms (50%) and rest amount provided by beneficiary/other scheme The detailed cost breakup duly verified by the administrative head of the concerned institution and the administrative head of the State Department concerned must be included in the project proposal.
HRDI	19	Kutki Cultivation under Atal Jari Buti Mission in Uttarakhand	Flexi fund	3 Year	278.00	Not Approved under RKVY.
	20	Strengthening of analytical and tissue culture laboratory at herbal research and development institute	Infrastr ucture	2 Year	225.00	Approved In Principle & Comments may be obtained from ICAR on the project first.
TDC	21	Subsidy on seed production treatment and training for financial year 2018-19- 2020-21	Flexi fund	3 Year	641.30	In Principle Approved with the condition that those component covered under SMSP scheme should be taken in SMSP component. Transport subsidy is supported for one year only under RKVY with the condition if transport subsidy not provided by any other scheme and resourses. Project may be restricted to the year 2019-20.
	22	Assistance on breeder seed purchase to strengthen the seed production chain in Uttarakhand for financial year 2018-19 -2020-21	Flexi fund	3 Year	5.36	In Principle Approved only oildseed crops is supported as per NMOOP norms and project duration May be recasted for 2 years.

Department	S. N.	Project Name	Stream	Project Duration Year	Approved Project Cost	Remarks
Sugar Cane	23	Enhancement productivity of sugar cane in Uttarakhnad	Flexi fund	1 Year	238.25	Not Approved
Total					5746.17	

A. Infrastructure and assets	=	**Rs. 5746.17**
(i) pre-harvest infrastructure	=	Rs. 1979.78 lakh
(ii) post-harvest infrastructure	=	Rs. 2489.41 lakh
(iii) Value addition linked production projects(agribusiness models	=	Rs. 0.00 lakh
(iv) Flexi fund	=	Rs. 1276.98 lakh
B. Special sub-schemes	=	Rs. 0.00 lakh
C. Innovation and agri-entrepreneur development	=	Rs. 0.00 lakh
Total (A+B+C)	=	**Rs. 5746.17 lakh**

एजेण्डा नं०–4 पोस्ट फैक्टो स्वीकृति एवं संशोधित धनराशि की स्वीकृति

(1) कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–9–56/2015– आर्गे. फार्मे., दिनांक 13 फरवरी, 2018 के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हेतु रू० 135.00 लाख केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित करते हुए रू० 150.00 लाख राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नार्मल आर.के.वी.वाई. से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए तथा निर्देश थे कि धनराशि की पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्राप्त करते हुए एस.एल.एस.सी. में इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। संबंधित परियोजना हेतु पोस्ट फैक्टो स्वीकृति लेते हुए रू० 150.00 लाख की धनराशि मार्च, 2018 में उपलब्ध करा दी गयी है। चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गयी।

(2) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–7–1/2018–आर.के.वी.वाई., दिनांक 07.06.2018 के द्वारा आकांक्षा जनपदों में नाडेप कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु रू० 28.00 लाख राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्राप्त करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। यह धनराशि भारत सरकार के मानकों के अनुसार नाडेप कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु चयनित आकांक्षा जनपद (हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर) को दी जा रही है। चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गयी।

(3) कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषक महोत्सव रबी 2017–18 हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा रू० 140.00 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी थी। परियोजना के कई मदों जैसे–प्रचार–प्रसार आदि में अनुमानित धनराशि रखी गयी थी। परियोजना पर रू० 145.00 लाख व्यय हुआ है। चर्चा के उपरान्त परियोजना की संशोधित लागत रू० 145.00 लाख पर सहमति प्रदान की गयी।

संबंधित विभाग परियोजनाओं के सम्पादन हेतु निम्न निर्देशों का भी पालन करेगें।

I. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की गाईडलाईन–रफ्तार में दिए गए निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य किए जाएं।

II. भारत सरकार के स्तर पर प्री–एस.एल.एस.सी. में परियोजनाओं के संबंध में दिए गए निर्देश/कमेन्ट्स में वर्णित मानकों को ध्यान में रखते हुए परियोजना मदों में कार्य किया जाए।

III. परियोजना के कार्य मदों में अनुदान एवं व्यय की जानी वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा।

IV. सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंन्ट रूल में दी गयी व्यवस्थाओं के तहत किया जाएगा।

V. किसी भी परियोजना में स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा तथा न ही स्वीकृत कार्य मदों से भिन्न मदों में कार्य किया जाएगा।

VI. किसी भी परियोजना में लम्बे समय तक धनराशि अवशेष न रखी जाए। समय से धनराशि का उपयोग कर लिया जाए।

VII. ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए जिनसे कृषकों की आय में वृद्धि होती है।

VIII. कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कलस्टर आधारित कृषि को प्राथमिकता दी जाए।

IX. परियोजना की गाईडलाईन के अनुसार प्रशासनिक व्यय केवल नोडल विभाग को देय होगा।

X. वर्तमान में संचालित परियोजनायें यथा सम्भव वर्ष 2019–20 तक पूर्ण कर ली जाएं।

सपोर्ट टू–स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्मर्स–आतमा अण्डर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्टेंशन (एस.एम.ए.ई.) एवं नेशन मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (एन.एम.ए.ई.टी) :

कृषि निदेशक द्वारा वर्ष 2017–18 में योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि तथा व्यय का विवरण रखा गया। योजना हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश रू० 864.65 लाख उपलब्ध कराया गया, जिसमें 10 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित करते हुए वर्ष हेतु कुल रू० 949.61 लाख उपलब्ध हुए। योजना में वर्ष 2016–17 की धनराशि रू० 253.61 लाख अवशेष थी, अवशेष धनराशि सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017–18 में कुल रू० 1203.22 लाख उपलब्ध हुआ। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू० 727.57 लाख का उपयोग मार्च 2018 तक कर लिया गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। अवशेष धनराशि रू० 475.65 लाख में से रू० 411.83 लाख का उपयोग माह जून 2018 तक कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया है, शेष धनराशि रू० 63.82 लाख का उपयोग माह अगस्त 2018 तक कर लिया जाएगा। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति संतोषजनक है।

अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या–9–28/2018–ए.ई. (एफ.टी.एस.पी. 51959), दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू० 874.70 लाख, जिसमें राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल अनुमानित परिव्यय रू० 971.89 लाख स्वीकृत किया गया। कृषि निदेशक द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु रू० 1455.24 लाख की योजना प्रस्तुत की गयी तथा अवगत कराया कि योजना का परीक्षण भारत सरकार के स्तर पर

कर लिया गया है, जिसकी सहमति भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (विस्तार विभाग) के पत्र संख्या–9–28/2018–ए.ई. (एफ.टी.एस. 57873), दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी है।

चर्चा के उपरान्त सपोर्ट टू–स्टेट एक्टेंशन प्रोग्राम फॉर एक्टेंशन रिफॉर्म्स–आतमा के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिए रू० 1455.24 लाख की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु/समीक्षा

(1) कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **एकीकृत कृषि कार्यों** की सफलता का प्रस्तुतीकरण वीडियो के माध्यम से किया गया, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के श्री प्रभाकर भाकुनी एवं श्रीमती पुष्पा कांडपाल द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया, कार्यक्रम प्रशंसनीय है। निर्देश दिए गए कि इसी प्रकार की सफलता की कहानियां अन्य जनपदों से भी तैयार की जाए, ताकि कृषकों में एक–दूसरे के कार्य को देखते हुए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

(2) सचिव पशुपालन द्वारा एफ.एम.डी. तथा भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी गयी। अवगत कराया गया कि योजना में तीन ब्रीडिंग फार्म केदारकांठा, पीपलकोटी एवं डुण्डा को विकसित किया जा रहा है, जिससे कृषकों को लाभ पहुंचा है। अहिल्या बाई होल्कर परियोजना से कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है। मत्स्य विभाग की परियोजना ट्राउट फार्मिंग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग एवं चमोली में स्थानों का चयन कर लाभार्थी कृषकों द्वारा वहां पर सहकारी समितियां बनाई गयी हैं।

(3) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषकों द्वारा मृदा परीक्षण की संस्तुति के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मैदानी क्षेत्र अग्रणीय है। नवम्बर 2017 से डी.बी.टी. के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार मृदा परीक्षण संस्तुति से उर्वरकों के प्रयोग तथा डी.बी.टी. द्वारा उर्वरक वितरण करने से लगभग 58000 मै० टन यूरिया की खपत कम हुई है। मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कारणों से उर्वरकों की अनावश्यक बिक्री कम हुई है। उर्वरकों के विक्रय की सूचना पोर्टल पर अपलोड होती है, जिन कृषकों द्वारा 100 से अधिक बोरी उर्वरक क्रय किए जाते हैं, उन कृषकों का सत्यापन प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कृषक एवं विक्रेता द्वारा उर्वरक का दुरूपयोग न किया जाए। अवगत कराया गया जहां यूरिया उर्वरक की खपत घटी है वहीं माइक्रोन्यूट्रेंट एवं अन्य उर्वरकों की खपत बढ़ी है।

(4) अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनपदों के प्रगतिशील कृषकों का व्हाटसएप ग्रुप बनाया जाए ताकि वह अपने विचार एक–दूसरे से साझा कर सके, इससे उनको सरकारी योजनाओं के साथ–साथ मार्केटिंग की भी जानकारी होगी। मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि हरिद्वार में इस प्रकार का व्हाटसएप ग्रुप बनाया गया है तथा कृषकों द्वारा ऑनलाईन मार्केटिंग की जा रही है।

(5) सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु 3900 कलस्टर प्राप्त हुए हैं, जिनके चयन की कार्यवाही गतिमान है, कलस्टरों का चयन कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जड़ी–बूटी शोध संस्थान एवं कैप द्वारा किया जा रहा है। अब तक 3500 कलस्टरों का चयन कर लिया गया है।

(6) यह भी अवगत कराया गया कि कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रू० 40.00 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें अधिक से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्देश दिए गए कि स्थानीय आवश्यकता, कृषकों की मांग एवं स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही फार्म मशीनरी बैंक में यंत्र क्रय किए जाएं।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1
संख्या– 1452 /XIII-1/2016-5(26)2008TC-III
देहरादून दिनांक 01 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव पशुपालन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. संयुक्त सचिव, आर०के०वी०वाई०, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
7. डा० तारसेम चन्द, संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
8. सलाहकार, कृषि नीति आयोग, नई दिल्ली।
9. प्रमुख सचिव/सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रमुख सचिव सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन/मत्स्य विकास उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उद्यान एवं फलोद्योग उत्तराखण्ड शासन।

14. प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास उत्तराखण्ड शासन।
15. संयुक्त निदेशक (प्रसार), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
16. अनुसचिव, (आर०के०वी०वाई०–अनुभाग), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
17. निदेशक, (आर०के०वी०वाई०), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
18. निदेशक शोध, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
19. निदेशक शोध, औद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
20. निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
21. जिलाधिकारी देहरादून/पौड़ी/उधमसिंहनगर/नैनीताल उत्तराखण्ड।
22. आयुक्त, गन्ना विकास एंव चीनी, उत्तराखण्ड, ऊधमसिंहनगर।
23. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
24. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोपरेटिव डेरी फेडरेशन मंगल पड़ाव, हल्द्वानी।
25. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम बीज भवन, पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली।
26. निदेशक, कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य पालन/डेरी विकास/रेशम विभाग/जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान उत्तराखण्ड।
27. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
28. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
29. मुख्य अधिशासी अधिकारी भेड़ एंव ऊन विकास परिषद् मोथरोवाला, देहरादून।
30. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
31. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एंव तराई विकास निगम, पंतनगर, हल्दी, उधसिंहनगर।
32. महानिदेशक एन.आई.आर.डी. एवं पंचायती राज राजेन्द्र नगर हैदराबाद, तेलांगना।
33. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कैप), सेलाकुई, देहरादून।
34. वैज्ञानिक सी मैप, हल्दी, पंतनगर, ऊधमसिंहनगर।
35. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(बी0एस0बोरा)
उप सचिव।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एस.एल.एस.सी. बैठक की उपस्थिति– दिनांक 19 जुलाई, 2018

क्र.सं.	नाम प्रतिभागी	पदनाम	विभाग का नाम
1.	डी० सेन्थिल पाण्डियन	सचिव	कृषि
2.	श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम	सचिव	पशुपालन
3.	श्री ललित मोहन रयाल	गन्ना आयुक्त	गन्ना एवं चीनी
4.	डा० तारसेम चन्द	संयुक्त सचिव	भारत सरकार
5.	श्री एस०ए० मुर्गेशन	जिलाधिकारी	देहरादून
6.	श्री गौरी शंकर	निदेशक	कृषि
7.	श्री ए०के०यादव	निदेशक	रेशम
8.	डा०के०के० जोशी	निदेशक	पशुपालन
9.	श्री जगदीश चन्द्र कैम	निदेशक	एच०आर०डी०आई०
10.	डा० बी०पी० मधवाल	निदेशक	मत्स्य
11.	डा०एम०एस० नयाल	मुख्य अधिशासी अधिकारी	यू०एल०डी०बी०
12.	श्रीमती कविता नबियाल	वित्त नियंत्रक	कृषि
13.	श्री अवनीश कुमार मिश्रा	डी.जी.एम.	मण्डी
14.	श्री अनिल कुमार	डी.जी.एम	मण्डी
15.	श्री के०सी० पाठक	अपर कृषि निदेशक	कृषि
16.	डा०ए०के०बिजोला	संयक्त निदेशक	पशुपालन
17.	श्री जयदीप अरोड़ा	संयुक्त निदेशक	डेयरी
18.	श्री ए०के०उपाध्याय	संयुक्त निदेशक	कृषि
19.	श्री दिनेश कुमार	संयुक्त निदेशक	कृषि
20.	श्री दिनेश वर्मा	संयुक्त निदेशक	नियोजन
21.	डा०एस०एस० सिंह	प्रोफेसर एवं हैड	के०वी०के० ढकरानी
22.	डा०अमोल वशिष्ठ	एशोसिएट डाईरेक्टर रिसर्च	औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय
23.	डा० आर०के० उपाध्याय	वैज्ञानिक	सी–मैप
24.	डा० वी०पी० भट्ट	वैज्ञानिक	एच०आर०डी०आई०
25.	श्री एम० एल० वर्मा	एरिया मैनेजर	एन०एस०सी०
26.	श्री एच०के० पुरोहित	उप निदेशक	मत्स्य
27.	श्री विनय कुमार	प्रबन्ध निदेशक	कृषि
28.	डा०वी०के०एस० यादव	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	कृषि
29.	डा० अजय सक्सेना	मुख्य कृषि अधिकारी उसिनगर	कृषि
30.	श्री जे०पी० भास्कर	स्टॉफ प्रोफेसर	लघु सिंचाई
31.	डा० दीपक पाण्डेय	मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी	टी०डी०सी०
32.	डा० सुनील शाह	वैज्ञानिक–सी	कैप, सेलाकुई
33.	डा० अविनाश आनन्द	सी.ई.ओ.	भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
34.	डा० ए०के० सिंह	सहायक कृषि अधिकारी	कृषि
35.	श्री शरद कुमार राजपूत	लेखाकार	कृषि